

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 28 AUGUST TO 03 SEPTEMBER 2024

■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 49 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside
News

FASTag बैलेंस
कम होने पर खुद ही ऐड
हो जाएगा पैसा,
आरबीआई ने कर दी
इसकी व्यवस्था



Page 2



1 सितंबर से बदल
रहे ये नियम

Page 4



हिज्बुल्लाह-
इजरायल जंग से मिडिल
ईस्ट में बढ़ा संकट



Page 5

editoria!

सौर ऊर्जा में बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ाने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। देश में 2070 तक उत्सर्जन को शून्य के स्तर तक लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम विभिन्न स्रोतों से पैदा होने वाले स्वच्छ ऊर्जा का अधिक से अधिक उत्पादन करें। इस पर जोर देने का ही नतीजा है कि भारत के कुल ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 19.5 प्रतिशत हो चुका है। यदि स्वच्छ ऊर्जा क्षमता की बात करें, तो उसमें यह हिस्सा 44 प्रतिशत से अधिक है। इस वर्ष के बजट में एक लाख करोड़ रुपये के एक अनुसंधान कोष की स्थापना की गयी है, जिसके अंतर्गत रक्षा, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र की निजी कंपनियों को स्वदेशी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी उपलब्ध करायी जायेगी। जनवरी 2023 में 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' का गठन किया गया, जिसके लिए पांच वर्षों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य तय किया गया है। बजट में सोलर सेल और पैनल के लिए जरूरी मुख्य चीजों पर सीमा शुल्क की छूट देने से उत्पादन खर्च में कमी आयेगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर पहल के अंतर्गत 1.3 करोड़ से अधिक पंजीकरण तथा 14 लाख से अधिक आवेदन जैसे आंकड़े इंगित करते हैं कि घरों पर सोलर पैनल लगाने में तेजी आयेगी। क्लिटिकल मिनरल्स मिशन से सौर, पवन, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी जैसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2014 से अब तक उत्पादन में 30 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सक्रियता बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस जलवायु सम्मेलन के बाद फ्रांस के साथ मिलकर सौर गठबंधन का गठन किया था, जिसमें सवा सौ से अधिक देश जुड़ चुके हैं। सौर ऊर्जा के साथ-साथ पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, एथेनॉल, बायोमास, जल विद्युत संयंत्र, कचरे से ऊर्जा निकालने आदि के संबंध में भी गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। निश्चित ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में यह एक उत्साहजनक परिदृश्य है।

कुलांचे मार रही इकॉनमी, घट रही महंगाई, जीएसटी कलेक्शन दमदार...

कितना रहेगा GDP ग्रोथ रेट

नई दिल्ली। एजेंसी

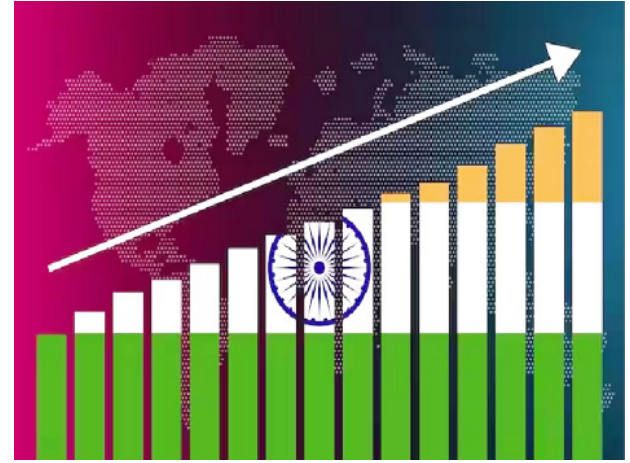
अनियमित मॉनसून के बावजूद भारत की आर्थिक गति बरकरार है और आर्थिक समीक्षा में 6.5 से 7.0% की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान सही जान पड़ता है। वित्त मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। जुलाई की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों में अपनी गति बनाए रखी है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार (अप्रैल-जुलाई) महीनों में जीएसटी कलेक्शन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह टैक्स बेस के विस्तार तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के दम पर मुमकिन हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के क्रय प्रबंधकों के सूचकांक के मजबूत प्रदर्शन से भी घरेलू गतिविधियों में मजबूती का पता चलता है। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि का कारण मांग का बढ़ना, नए निर्यात ऑर्डर में तेजी तथा उत्पादन कीमतों

का बढ़ना है। राजकोषीय मोर्चे पर इसमें कहा गया कि बजट वित्त वर्ष 2024-25 ने राजकोषीय मजबूती का मार्ग प्रशस्त किया है। मजबूत राजस्व संग्रह, राजस्व व्यय में अनुशासन तथा मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के समर्थन से राजकोषीय घाटे में कमी आने का अनुमान है। साथ ही, इसमें कहा गया कि पूंजीगत व्यय को उच्च स्तर पर बनाए रखा गया है, जिससे नए निजी निवेश चक्र को समर्थन मिल रहा है।

क्यों घटी महंगाई

रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा महंगाई जुलाई 2024 में घटकर 3.5% रह गई जो सितंबर 2019 के बाद सबसे कम है। यह खाद्य महंगाई में नरमी का नतीजा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून में स्थिर प्रगति ने खरीफ की बुवाई का समर्थन किया है। इसमें कहा गया है कि जलाशयों में जल स्तर का फिर से बढ़ना मौजूदा खरीफ तथा आगामी रबी फसल के उत्पादन के लिए अच्छा संकेत है। इससे आने वाले महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में कहा गया कि कुल मिलाकर



भारत की आर्थिक गति बरकरार है। कुछ हद तक अनियमित मानसून के बावजूद जलाशयों में जलस्तर की भरपाई हो गई है। क्रय प्रबंधकों के सूचकांक के अनुसार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है। इसमें कहा गया कि कर संग्रह, खासकर अप्रत्यक्ष कर (जो लेन-देन को दर्शाते हैं) अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, तथा बैंक ऋण भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार

महंगाई कम हो रही है और वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है। शेयर बाजार अपने स्तर पर बने हुए हैं। सकल प्रवाह बढ़ने के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है। फिलहाल 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5-7.0% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान उचित जान पड़ता है।

उद्योगों की समस्याओं को समग्रता से सोचकर हल करेंगे- महापौर

उद्योगों की कमेटी बनाकर हर 15 दिन में निगरानी, समस्याओं का निदान करने की ने की घोषणा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

उद्योगपतियों मध्य आज महापौर माननीय श्री पुष्पमित्र भार्गव जी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आपके क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उन पर समग्रता से सोचें और एक एक कर सभी का हल होगा। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि निगम अनदेखी कर रहा है हम प्रयासरत हैं और सभी समस्याओं का निदान होगा ऐसा आपने आश्वासन दिया। एसोसिएशन के सेक्टर सी सांवर रोड के स्ट्रीट लाइट के प्रस्ताव पर आपने सहमति से के साथ स्वीकृति दी की आप सेक्टर सी के अलावा अन्य किसी भी सेक्टर में लाइट लगाये बिजली का बिल नगर निगम भरेगा। सभी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्थाएं



जल्द ही करने के साथ साथ आपने अतिक्रमण की समस्या के हल हेतु सर्वे कर प्लान बनाने के आदेश दिये। आपने पालदा के बुनियादी विकास के लिए उद्योगपतियों से उनका 40 प्रतिशत अंशदान जमा करने को कहा। आपने कहा कि सडक के साथ स्टॉर्म वाटर लाइने व ड्रेनेज निगम द्वारा डाली जायेगी। सम्पत्तिकर की विसंगतियों के लिए आपने एसोसिएशन में केम्प आयोजित करने की भी स्वीकृति दी। आपने कहा कि नगर निगम को 2026 तक पूर्णतः डिजिटलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। आपने समन्वय समिति के गठन करने के प्रति आश्वासनकर 15 दिन में बैठक कर निगरानी करने का भी भरोसा दिलाया।

रूस के साथ लड़ाई में बर्बाद हो गया यूक्रेन! बन गया यूरोप का सबसे गरीब देश

नई दिल्ली। एजेंसी

रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था और तबसे दोनों देशों के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई ने यूक्रेन को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। काम धंधा ठप पड़ा है और लाखों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। लोगों को पानी और खाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। इस लड़ाई ने लाखों लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। हालत यह हो गई है कि यूक्रेन यूरोप का सबसे गरीब देश बन गया है। आईएमएफ के मुताबिक यूक्रेन की प्रति व्यक्ति आय 4,500 डॉलर रह गई है। मोल्दोवा की भी यही स्थिति है। ये दोनों देश यूरोप के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। यूरोप के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में कोसोवो तीसरे नंबर पर है। वहां की जीडीपी पर कैपिता 4,700 डॉलर है। इसके बाद आर्मेनिया, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, जॉर्जिया, बोस्निया एंड हर्जगोविना, सर्बिया और मोन्टेनेग्रो का नंबर है। इन देशों की जीडीपी पर कैपिता 5,300 डॉलर से 8,000 डॉलर के बीच है। इस लिस्ट में तुर्की (12,500 डॉलर) 15वें और रूस 13,500 डॉलर जीडीपी पर कैपिता के साथ 16वें पर हैं। कई साल से आर्थिक बदहाली से जूझ रहा ग्रीस 17वें नंबर पर है। ग्रीस की जीडीपी पर कैपिता 14,800 डॉलर है। हंगरी, क्रोएशिया और पुर्तगाल भी टॉप 20 गरीब देशों की लिस्ट में शामिल हैं।



नई दिल्ली। एजेंसी

प्रोविडेंट फंड (PF) क्लेम का सेटलमेंट अब आसान होने वाला है। सूत्रों ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपना अपग्रेड किया गया सिस्टम, EPFO आईटी सिस्टम 2.01 लॉन्च करने जा रहा है। यह कदम ईपीएफओ के मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स

के लिए सर्विसेस को ज्यादा आसान और इफेक्टिव बनाने के लिए उठाया जा रहा है। नया सिस्टम आने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करने से लेकर क्लेम करने और सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया पहले से आसान हो जाएगी। नया सिस्टम आने पर नौकरी बदलने पर सदस्य आईडी (MID) के ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होगी।

EPFO क्लेम के लिए अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, जानिए क्या है सरकार का प्लान

कब होगा शुरू?

सूत्रों ने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को आईटी सिस्टम के आधुनिकीकरण इनिशिएटिव की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि नया सिस्टम तीन महीने के अंदर चालू हो जाएगा। नए सिस्टम से EPFO ग्राहकों के लिए यूजर एक्सपीरियंस काफी बेहतर होने की उम्मीद है। इस बदलाव में पेमेंट और क्लेम निपटान के लिए एक सुव्यवस्थित और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम शामिल होगा।

क्या होंगे बदलाव?

एक सूत्र ने कहा, इस सिस्टम

में पेंशन का वितरण सेंट्रलाइज्ड होगा और मंथली आधार पर किया जाएगा। इस नए सिस्टम से सेंट्रलाइज्ड क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा, जिसमें क्लेम्स की पूरी तरह से ऑटोमैटिक प्रोसेसिंग, सेंट्रलाइज्ड मंथली पेंशन डिस्ट्रिब्यूशन और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधारित ईपीएफ अकाउंटिंग शामिल हैं।

क्या होगा फायदा?

EPF अकाउंटिंग सिस्टम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पर आधारित होगा। इससे सदस्यों के लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिसिट

का फिर से गठन किया जाएगा। इसके अलावा, जॉब बदलने पर मेंबर आईडी (MID) के ट्रांसफर की जरूरत को भी खत्म कर दिया जाएगा। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए EPFO ने पहले ही सरल आईटी प्रोसेस शुरू कर दी हैं। इसमें 1 लाख रुपये तक के सभी प्रकार के EPF अडवांस क्लेम की ऑटो-मोड प्रक्रिया शामिल है।

क्या थी शिकायत?

EPFO से जुड़े सदस्यों की शिकायत रही है कि पोर्टल पर एक बार लॉगिन नहीं होता है। अगर लॉगिन हो भी जाता है तो

फिर से KYC अपडेट मांगता है, जबकि यह पहले भी कई बार किया जा चुका है। सबसे ज्यादा शिकायतें सर्वर के धीमा काम करने को लेकर हैं, जिसके चलते EPFO के सदस्य धनराशि निकालने के लिए क्लेम भी नहीं कर पाते हैं। पिछले साल जुलाई में, ईपीएफओ के कुछ अधिकारियों ने केंद्र सरकार को लैटर लिखकर पुराने और कमजोर सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में शिकायत की थी, जिससे कस्टमर्स को काफी प्रॉब्लम्स हो रही थीं। इसे देखते हुए ईपीएफओ के आईटी सिस्टम को सुधारने और नए प्लैटफॉर्म पर स्मूथ शिफ्टिंग के लिए यह कदम उठाया गया है।

क्रिप्टो वर्ल्ड में मची तबाही, बिटकॉइन से लेकर डॉगेकॉइन तक... सब हुए धड़ाम

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकॉर्सेसी बिटकॉइन की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन के दाम 60 हजार डॉलर से नीचे आ गए हैं। कॉइनमार्केट कैप के डाटा के अनुसार बीते 24 घंटे में बिटकॉइन की कीमत में 5.61 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। भले ही शेयर बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ हो, लेकिन क्रिप्टोकॉर्सेसी मार्केट बुधवार को धड़ाम हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकॉर्सेसी बिटकॉइन से लेकर इथेरियम और डॉगेकॉइन तक में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। इस गिरावट की वजह? ग्लोबल क्रिप्टोकॉर्सेसी का मार्केट कैप में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। कई महीनों के बाद बिटकॉइन के दाम 60 हजार डॉलर से नीचे आ गए हैं। जानकारों की मानें तो इस गिरावट को यूएस का जीडीपी डाटा आने के रूप में देखा जा रहा है।

60 हजार डॉलर से नीचे आया बिटकॉइन

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकॉर्सेसी बिटकॉइन की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन के दाम 60 हजार डॉलर से नीचे आ गए हैं। कॉइनमार्केट कैप के डाटा के अनुसार बीते 24 घंटे में बिटकॉइन की कीमत में 5.61 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकॉर्सेसी की कीमतें 59,269.04 डॉलर पर आ गई हैं। वैसे बीते एक घंटे के कारोबार में बिटकॉइन की कीमतों में एक फीसदी से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली है।

वहीं दूसरी ओर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकॉर्सेसी इथेरियम की कीमतों में भी 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और कीमतें 2500 डॉलर से नीचे आते हुए 2464 डॉलर पर आ गई हैं। वैसे कीमतों में एक फीसदी की रिकवरी करीब एक घंटे में देखने को मिली है।

डॉगेकॉइन और शिबा इनु में भी गिरावट

दुनिया की पॉपुलर वर्चुअल करेंसी में शुमार डॉगेकॉइन और शिबा इनु में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में डॉगेकॉइन की कीमत में 6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बीते एक घंटे में कीमतों में एक फीसदी से ज्यादा की रिकवरी देखी गई है। शिबा इनु की कीमतों में भी 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। जानकारों की मानें तो दोनों छोटी क्रिप्टोकॉर्सेसी में और ज्यादा की गिरावट देखी जा सकती है।

इन करेंसीज में भी बड़ी गिरावट

मौजूदा समय में सोलाना में 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर एवालॉशे में भी 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। चैनलिंग और पोलकाडॉट में भी करीब 5 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है। नियर प्रोटोकॉल में करीब 8 फीसदी और पॉलिगन में 12 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है। कैस्पा में करीब 6 फीसदी और यूनिस्वैप में करीब 11 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है। पेपे और रेंडर जैसे कॉइन में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।

प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर, दुनिया का दूसरा सबसे महंगा भारत का यह शहर बड़ी-बड़ी हस्तियां रहती हैं यहां

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया में प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है। कोरोना के बाद से प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आ गया है। वहीं दूसरी ओर अब लोग अफोर्डेबल हाउस की जगह बड़ों घरों और प्राइम लोकेशन को तवज्जो दे रहे हैं। इस बीच एक इंडेक्स के मुताबिक फिलीपींस की राजधानी मनीला प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी के मामले में दुनिया की सबसे महंगा शहर बन गया है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के मुताबिक मनीला में प्रॉपर्टी की कीमतों में 26 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा जून में समाप्त तिमाही का है।

इस इंडेक्स में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई दूसरे स्थान पर रही। सबसे महंगी प्रॉपर्टी के मामले में मुंबई दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इसमें 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मुंबई में मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसी प्रमुख हस्तियां रहती हैं। इस इंडेक्स में दुनिया के 44 शहरों

को शामिल किया गया था। इन शहरों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, उससे पता चलता है कि इन प्राइम लोकेशन पर घरों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इस इंडेक्स में पिछले साल मुंबई 6वें स्थान पर थी।



दिल्ली में भी बड़ी मांग

प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमत के मामले में दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर भी पीछे नहीं हैं। इन शहरों में भी प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी की मांग में बढ़ोतरी जारी है। इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली में प्राइम लोकेशन की कीमतों में सालाना 10.6 फीसदी और बेंगलुरु में 3.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडेक्स में दिल्ली एक साल पहले 26वें स्थान के मुकाबले जून तिमाही में तीसरे स्थान पर रही। वहीं बेंगलुरु ने अपना

15वां स्थान बनाए रखा। प्रीमियम सेगमेंट में भी भारी डिमांड

प्राइम लोकेशन के अलावा प्रीमियम सेगमेंट में भी प्रॉपर्टी की मांग बढ़ी हुई है। नाइट फ्रैंक इंडिया के सीएमडी शिशिर बैजल ने कहा कि भारतीय बाजार में प्रीमियम

सेगमेंट में घरों की बिक्री की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में अमीरों की बढ़ती दौलत और लाइफस्टाइल के चलते प्रीमियम सेगमेंट में घरों की बिक्री की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई की यह गति आगे भी जारी रहेगी।

ये हैं प्राइम लोकेशन

मुंबई और दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जो प्राइम लोकेशन पर हैं। मुंबई की बात करें तो प्राइम लोकेशन में प्रमुख नाम बांद्रा वेस्ट, मालाबार हिल्स, अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट, बोरीवली, गोरेगांव वेस्ट आदि हैं। वहीं दिल्ली में कुछ प्राइम लोकेशन के नाम पृथ्वीराज रोड, जोर बाग, डिफेंस कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, पंजाबी बाग, पंचशील पार्क, लुटियंस जोन, वसंत कुंज, साकेत, मॉडल टाउन आदि हैं।

FASTag बैलेंस कम होने पर खुद ही ऐड हो जाएगा पैसा, आरबीआई ने कर दी इसकी व्यवस्था

नई दिल्ली। एजेंसी

RBI ने अपने ई-मैनेज्ड फ्रेमवर्क में एक अपडेट की घोषणा की है। RBI ने फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) की ऑटो-रिप्लेनिशमेंट को ई-मैनेज्ड फ्रेमवर्क के तहत शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे यूजर्स FASTag बैलेंस तय सीमा से नीचे जाने पर ऑटोमैटिकली पैसा ऐड कर पाएंगे। मतलब जब बैलेंस ग्राहक द्वारा तय सीमा से कम हो जाता है, तो ई-मैनेज्ड ऑटोमैटिक रूप से फास्टैग और NCMC की भरपाई कर देगा। ई-मैनेज्ड फ्रेमवर्क को 2019 में स्थापित किया गया था। इसका मकसद कस्टमर्स को उनके अकाउंट्स से होने वाले

डेबिट की जानकारी देकर उनके हितों की रक्षा करना है। RBI ने एक सर्कुलर में कहा कि फास्टैग और NCMC में बैलेंस की ऑटो-रिप्लेनिशमेंट, जो ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से कम होने पर ट्रिगर हो जाती है, अब मौजूदा ई-मैनेज्ड फ्रेमवर्क के तहत आएगी। ये ट्रांजैक्शन रेकरिंग होने के कारण, वास्तविक शुल्क से 24 घंटे पहले ग्राहकों को प्री-डेबिट नोटिफिकेशन भेजने की आवश्यकता से मुक्त होंगे। जून में आरबीआई ने फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को ऑटो पेमेंट मोड में लाने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा ई-मैनेज्ड ढांचे के तहत ग्राहक के खाते से पैसे निकालने से कम से कम 24 घंटे पहले इसकी सूचना देने की आवश्यकता होती है।



क्या है ई-मैनेज्ड

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जून में कहा था कि ई-मैनेज्ड यानी भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मंजूरी के तहत अभी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि जैसे निश्चित अवधि वाली सुविधाओं के लिए निश्चित समय पर ग्राहक के खाते से भुगतान स्वयं हो जाता है। अब इसमें ऐसी सुविधाओं और प्लेटफॉर्मों को जोड़ा जा रहा है जिनके लिए भुगतान का कोई समय तय नहीं है जबकि भुगतान जमा राशि कम होने पर किया जाता है। ई-मैनेज्ड ग्राहकों के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल भुगतान सेवा है। इसकी शुरुआत 10 जनवरी, 2020 को की गई थी।

जमा पैसे पर ब्याज, रु.2 लाख का बीमा, बड़े काम का सरकार का यह अकाउंट

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई योजना-प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई योजना- प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे हो गए हैं। साल 2014 में गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले जा चुके हैं।



बता दें कि योजना से जुड़े अकाउंटहोल्डर्स को कई बड़े फायदे मिलते हैं। आइए इसकी डिटेल्ड जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र आउटलेट में खोला जा सकता है। योजना के तहत अकाउंटहोल्डर को डिपॉजिट

रकम पर ब्याज की सुविधा मिलती है। इसने पात्र लाभार्थियों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित, निर्बाध तथा पारदर्शी हस्तांतरण संभव बनाया है और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है।

53 करोड़ अकाउंट खोले

बता दें कि जनधन खातों के जरिये 53 करोड़ लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल हुए हैं। इन बैंक खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि जमा हुई है और इसके साथ ही 36 करोड़ से अधिक निःशुल्क रुपये कार्ड जारी किए गए हैं, जिन पर दो लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवर भी

मिलता है। इसमें खाता खोलने का कोई शुल्क या रखरखाव शुल्क नहीं है और न्यूनतम शेषराशि रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इन अकाउंट में 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं और 55 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते न केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त करने में सहायक रहे हैं, बल्कि ये बिना किसी बिचौलिये के सरकार द्वारा इच्छित लाभार्थी को परेशानी मुक्त सब्सिडी / भुगतान, निर्बाध लेनदेन और बचत संचय के लिए एक मंच के रूप में भी काम करते हैं।

10 राज्यों में बनेंगी 12 Industrial Smart City कैबिनेट ने लगाई मुहर

नई दिल्ली। एजेंसी

बुधवार को दिल्ली में कैबिनेट और सीसीईए की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। कैबिनेट ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट और 234 नए शहरों के लिए प्राइवेट एफएम प्रोजेक्ट पर भी मुहर लग गई।

इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (National Industrial Corridor Development Programme) के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रोजेक्ट के लिए 28602 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। भारत की ग्लोबल वैल्यू चेन की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार स्मार्ट

इंडस्ट्रियल सिटी या इंडस्ट्रियल नोड्स की तैयार जमीन निवेशकों को ऑफर करेगी।

कहां बनेंगे स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी

देश के 10 राज्यों में 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य 6 कॉरिडोर को स्थापित किया जाएगा। इन शहरों में बनेंगे स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी उत्तराखंड में स्थित खुरपिया पंजाब में स्थित राजपुरा पटियाला महाराष्ट्र में दिश्री केरल में पलक्कड़ उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज बिहार में गया तेलंगाना में जहिराबाद आंध्र प्रदेश में ओरक्कल और कोपारत्थी

राजस्थान में जोधपुर पाली

यह सभी सिटी पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के दिशा के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इन सिटी में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा। यह स्मार्ट सिटी प्लग एंड प्ले और वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को इस तरह तैयार किया जाएगा जिससे निवेशकों को इन सिटीज में काम शुरू करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

टैक्सपेयर्स से कैसे पेश आना है... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों को दिया मंत्र

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स अधिकारियों से कहा कि वे टैक्सपेयर्स को भेजे जाने वाले नोटिस में सरल शब्दों का इस्तेमाल करें और कानून की तरफ से दी गई शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें। सीतारमण ने 165वें इनकम टैक्स डे के मौके पर बुधवार को आयोजित एक समारोह में कहा कि फेसलेस एसेसमेंट सिस्टम लागू होने के बाद टैक्स अधिकारियों को अब टैक्सपेयर्स के साथ अधिक निष्पक्ष

और मैत्रीपूर्ण व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैक्स नोटिस से टैक्सपेयर्स के मन में डर की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए। टैक्स नोटिस सरल और साफ होना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटिस में करदाता को यह एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसे किस कारण से नोटिस भेजा जा रहा है। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि आयकर रिफंड तेजी से जारी करने में सुधार की गुंजाइश है। सीतारमण ने करदाताओं के साथ व्यवहार में

अनियमित तरीके अपनाने से बचने का टैक्स अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि उनकी कार्यवाही मुद्दे के अनुपात में ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनफोर्समेंट उपायों का उपयोग केवल अंतिम माध्यम के रूप में होना चाहिए और विभाग का लक्ष्य स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने का होना चाहिए।

सरल भाषा में नोटिस

इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि कर विभाग को अधिक मित्रवत और पारदर्शी होने की उनकी बात का

मतलब यह नहीं है कि टैक्स अधिकारी का व्यवहार पहले अनुचित था। उन्होंने कहा, 'क्या हम सरल और समझने में आसान नोटिस भेजने के बारे में सोच सकते हैं? आप कारण बताएं कि नोटिस में कार्यवाही क्यों की गई और नोटिस क्यों भेजा जा रहा है।' वित्त मंत्री ने टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपना समर्थन जताते हुए कहा कि टैक्स अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखना चाहिए।

ऑक्सफोर्ड एवं इंदौर इंटरनैशनल कॉलेज के समूह निदेशक डॉ. पुनीत द्विवेदी एवं इंदौर इंटरनैशनल कॉलेज की प्राचार्या डॉ. नेहा शर्मा को 'इंस्पायरिंग लीडर्स एवार्ड'

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

उद्यमिता, नवाचार एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभाने वाले इंदौर के शिक्षाविद ऑक्सफोर्ड इंटरनैशनल कॉलेज एवं इंदौर इंटरनैशनल कॉलेज के समूह निदेशक एवं स्टार्टअप मेंटर डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी को

मुंबई में आयोजित 'इंस्पायरिंग लीडर्स एवार्ड-2024' कार्यक्रम में 'इंस्पायरिंग लीडर्स एवार्ड' सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इंदौर इंटरनैशनल कॉलेज की प्राचार्या डॉ. नेहा शर्मा चौधरी को भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र एवं करियर मार्गदर्शन में महती भूमिका निभाने हेतु



'इंस्पायरिंग लीडर्स एवार्ड-2024' से सम्मानित किया गया। अवार्ड सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में शादी डॉट कॉम के संस्थापक एवं देश के जाने माने स्टार्टअप निवेशक एवं शॉक टैंक कार्यक्रम के शॉक श्री अनुपम मित्तल उपस्थित रहे। श्री अनुपम मित्तल ने डॉ. पुनीत द्विवेदी एवं डॉ. नेहा शर्मा चौधरी को इंस्पायरिंग लीडर्स एवार्ड से सम्मानित किया। यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया कि डॉ. द्विवेदी द्वारा 23 पुस्तकों का लेखन किया गया है

एवं 25 के लगभग पेटेंट्स का पब्लिकेशन किया गया है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित डॉ. पुनीत द्विवेदी इंदौर स्वच्छता अभियान के विगत सात वर्षों से ब्रांड एंबेसडर हैं तथा उद्यमिता विकास के क्षेत्र में महती भूमिका निभा रहे हैं। डॉ. पुनीत द्विवेदी उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवंतिका विश्वविद्यालय उज्जैन में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य है। वहीं शिक्षाविद डॉ. नेहा शर्मा चौधरी प्रबंधकीय शिक्षा एवं विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन हेतु 1500 के लगभग करियर मार्गदर्शन सत्रों का आयोजन कर उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के

मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉ. नेहा शर्मा चौधरी द्वारा भी कई पेटेंट्स एवं पुस्तकों का लेखन किया गया तथा कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मानों से डॉ. नेहा शर्मा सम्मानित हो चुकी है। डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी एवं डॉ. नेहा शर्मा चौधरी की इस उपलब्धि पर संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट अक्षांशु तिवारी ने बधाई प्रेषित की एवं उद्यमिता एवं कौशल विकास से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन संभव है, की वकालत की।

प्लास्ट टाइम्स

व्यापार की बुलंद आवाज

अपनी प्रति आज ही बुक करवाएं

विज्ञापन के लिए संपर्क करें।

83052-99999

indianplasttimes@gmail.com



नई दिल्ली। एजेंसी

गूगल, आधार कार्ड और मैसेजिंग-कॉलिंग के नियमों में बदलाव हो रहा है। इसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स पर पड़ने वाला है। ऐसे में आपको इन बदलाव की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप समय पर अपने काम पूरे कर पाएंगे। जिन नियमों में बदलाव हो रहा है, उसमें Google Play store पॉलिस्सी, NPCI, UIDAI और TRAI के नियम शामिल हैं।

बदलने जा रहे ये नियम

TRAI की तरफ से फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को 30 अगस्त की डेडलाइन दी गई है। साथ ही आधार अपडेट को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा गूगल अपने प्लेटफॉर्म से कुछ ऐप्स को हटा रहा है। वही अगर आप यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल कर करते हैं, तो आपके लिए जरूरी सूचना है।

गूगल प्ले स्टोर से इन ऐप्स की होगी छुट्टी?

गूगल की नई प्ले स्टोर पॉलिस्सी को 1 सितंबर 2024 से लागू किया जा रहा है। इसका सीधा अगर आम यूजर्स पर देखने को मिलेगा। गूगल का कहना है कि वो 1 सितंबर से गूगल अपने प्ले स्टोर से हजारों ऐसे ऐप्स की छुट्टी करने जा रहा है, जो लो क्वालिटी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। गूगल का मानना है कि ये ऐप्स मैलवेयर सोर्स हो सकते हैं। ऐसे में गूगल क्वालिटी कंट्रोल की ओर से ऐसे सभी ऐप्स को हटाने का निर्देश दिया गया है। इससे दुनियाभर में एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं। गूगल का कहना है कि उसकी तरफ से यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मद्देनजर ऐसा फैसला किया गया है।

फ्री आधार कार्ड अपडेट?

आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ

1 सितंबर से बदल रहे ये नियम उदुत, Aadhaar, UPI और मोबाइल यूजर्स पर होगा असर

इंडिया यानी UIDAI की तरफ से मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया गया है, जो पहले तक 14 जून 2024 हुआ करती थी। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है, तो उसे 14 सितंबर से पहले फ्री में अपडेट कर सकते हैं। हालांकि फ्री आधार कार्ड अपडेट My Aadhaar पोर्टल से होगा। अगर आप आधार सेंटर पर जाकर आधार अपडेट करते हैं, तो आपको सर्विस चार्ज के तौर पर 50 रुपये देने होंगे। यूजर्स फ्री आधार अपडेट की सुविधा का लुफ्त केवल ऑनलाइन मोड में उठा सकते हैं।

कैसे फ्री आधार करें अपडेट सबसे पहले आपको UIDAI

की ऑफिशियल वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in/ पर विजिट करना होगा।

इसके बाद आपको टॉप में Update Aadhaar के ऑप्शन दिखेगा, जिस पर टैप करना होगा।

फिर आपको अपना 10 डिजिट आधार नंबर और ओटीपी डालकर पोर्टल को लॉगिन करना होगा।

फिर डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करके वेरिफाई करना होगा।

ड्रॉप डाउन मेन्यू में पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की स्कैन अपलोड करना होगा।

इसके बाद आपको एल्सू बटन पर क्लिक करना होगा। आपको एक रिविस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा।

इसके बाद आप आधार अपडेट

का स्टेटस चेक कर पाएंगे।

मैसेज और ओटीपी मिलने में होगी देरी

ट्राई ने 1 सितंबर से फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के निर्देश दिये हैं। इसके तहत टेलिकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, जियो और बीएसएनएल को अन-रजिस्टर्ड मैसेज और कॉल को पहचान करके ब्लॉक करना होगा। इसके लिए 30 सितंबर 2024 की डेडलाइन दी गई है। ऐसे में 1 सितंबर से कुछ मोबाइल यूजर्स को बैंकिंग कॉल, मैसेज और ओटीपी मिलने में देरी हो सकती है। ट्राई ने 1 सितंबर 2024 से यूआरएल, ओटीटी लिंक, एपीके (एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज), या कॉल-बैक नंबर वाले मैसेज को ब्लॉक करने

के निर्देश दिये हैं। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ओटीपी बेस्ड पेमेंट या डिलीवरी करते हैं, तो आपको ओटीपी मिलने में देरी हो सकती है, ऐसे में आपको ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कामकाज में दिक्कत पैदा हो सकती है।

रुपे कार्ड रिवाइड प्वाइंट?

NPCI के नए नियम के मुताबिक, अब रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस आपके रुपे रिवाइड प्वाइंट से नहीं काटे जाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंकों को इस मामले में सूचना दे दी गई है। NPCI का यह नया नियम 1 सितंबर 2024 से देशभर में लागू हो जाएगा।

टेलीग्राम समेत कई मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर दुबई में क्यों हैं

इस शहर में है क्या खास

एजेंसी

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पिछले साल की शुरुआत में एक महत्वाकांक्षी दुबई इकोनॉमिक एजेंडा 'डी33' लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य अगले दशक में दुबई की अर्थव्यवस्था के आकार को दोगुना करने और दुनिया के तीन बड़े शहरों में उसकी स्थिति मजबूत करना था। नए दुबई इकोनॉमिक एजेंडे में 100 परिवर्तनकारी परियोजनाएं शामिल हैं। 'डी33' का लक्ष्य अमीरात के विदेशी व्यापार को दोगुना कर एईडी 25.6 ट्रिलियन तक पहुंचाना और अगले दशक में 400 शहरों को प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में जोड़ना है। 'डी33' के लॉन्च के समय यूएई के शासक और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद ने कहा था, 'साल 2033 में दुबई की स्थापना के 200 साल पूरे होंगे। उस समय दुबई सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल बिजनेस सेंटर होगा।'

इन दिनों दुबई के चर्चा में आने की वजह है टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप. टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल दुरोव को तीन दिन पहले एक आपराधिक मामले में पेरिस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। टेलीग्राम कंपनी का हेडक्वार्टर दुबई में है। इससे एक बात और सामने आ रही है कि आखिर क्यों दुबई मल्टी नेशनल कंपनियों (एचएनएल) और अन्य औद्योगिक घरानों के लिए पसंदीदा जगह बनती जा रही है। 'डी33' लॉन्च होने के बाद से पिछले डेढ़ साल में कई कंपनियों और पारिवारिक कारोबारियों ने अपने ग्लोबल ऑफिस या हेडक्वार्टर दुबई में स्थानांतरित कर दिए हैं।

इन बड़ी कंपनियों के दुबई में हैं ऑफिस

डेल, एचपी, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के ऑफिस दुबई में हैं। इतना ही नहीं 100 से ज्यादा स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के भी वहां पर कार्यालय हैं। आईटी कंपनियों की बात करें तो दुबई आईबीएम, गूगल, केएनजेड सॉल्यूशन, वन



पैसिब, एमेजन, ब्रेनवायर, कागनीजेंट, विप्रो, एचसीएल, ओरेकल, माइंटट्टी और क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनियों का घर है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दुबई के लिए सबसे ज्यादा रवेन्यू पैदा करने वाले उद्योगों में से एक है। क्योंकि देश में एयरपोर्ट और बंदरगाह दोनों हैं। यह शहर पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित है, इसने इसे बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आदर्श स्थान बना दिया है।

फैसला किया कि आगे बढ़ना है

एक रिपोर्ट के अनुसार दुबई फाइनेंशियल मार्केट के अध्यक्ष, अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग

के महानिदेशक हेलाल सईद अलमरी ने कहा कि अमीरात ने अपने अंदर देखने का फैसला किया कि कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि दुबई कोविड के बाद के युग में और 33 एजेंडा के हिस्से के रूप में बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दुबई ने यह भी देखा कि अधिक प्रतिस्पर्धी होने के लिए लंबी अवधि में लागत का प्रबंधन कैसे किया जाए, मांग और आपूर्ति का प्रबंधन किया जाए। सुरक्षा और सहनशीलता के पहलुओं का भी आकलन किया जाए।

काफी कंपनियों ने दुबई को चुना

अलमरी ने कहा, 'आज, हम

इसको देख रहे हैं। पिछले 20 महीनों में, कई कंपनियों ने दुबई को अपने इंटरनेशनल सेंटर के रूप में चुनने और दुबई से दुनिया भर में बिजनेस चलाने का निर्णय लिया। उनमें से कुछ कंपनियों ने पहली बार अपने घरेलू बाजार छोड़ने का निर्णय लिया। हमने यह भी देखा है कि कई उद्यमियों ने दुबई जाने या यहां रहने करने का फैसला किया है।' यह महत्वपूर्ण है कि अगर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं यहां रहना और काम करना चाहती हैं और यहां कुछ नया करना चाहती हैं। क्योंकि तब संभावना अधिक है कि जब कॉर्पोरेट और अन्य सभी प्रकार की कंपनियां सफल होंगी।

120 से अधिक धनी परिवारों का घर

मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया (एमईएसए) क्षेत्र में अग्रणी वैश्विक वित्तीय केंद्र, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) ने कहा कि अमीरात दुनिया के 120 से अधिक सबसे धनी परिवारों और व्यक्तियों का घर है, जिनकी कुल संपत्ति एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की है। इसमें कहा गया है कि डीआईएफसी ने दुबई को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया

क्षेत्र में नंबर एक शहर और सबसे धनी आबादी के मामले में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 22 शहरों में स्थान दिलाने में मदद की है। दुबई ने कोविड के बाद की अवधि में, खासकर गोलडन वीजा की शुरुआत के बाद, दुनिया भर से प्रोफेशनल्स और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित किया है। जबकि बिजनेस करने में आसान के नियमों ने कई कंपनियों को दुबई में स्थानांतरित होने के लिए आकर्षित करने में मदद की।

बिजनेस और हेल्थ टूरिज्म में अव्वल

दुबई ने पिछले 20 महीनों में बहुत सारे ग्लोबल ट्रेंड देखे हैं। जिससे इसे बढ़ने में मदद मिली है। लोग दुबई को केवल टूरिज्म के लिए ही सोचते हैं। दुबई बिजनेस और हेल्थ टूरिज्म क्षेत्र में भी नंबर एक है। अमीरात के पास सही निगरानीकर्ता, सिस्टम और नियम हैं और इसके परिणामस्वरूप दुबई में तमाम क्षेत्रों की कंपनियां मौजूद हैं। दुबई के आकर्षण का एक बड़ा कारण बिजनेस फ्रेंडली माहौल है। कर्मचारियों के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है, बिजनेस के लिए भी टैक्स कम है और एक्साइज ड्यूटी नदारद है।

हिज्बुल्लाह-इजरायल जंग से मिडिल ईस्ट में बढ़ा संकट

भारत के सामने होंगी ये चुनौतियां

नई दिल्ली। एजेंसी

हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष से भारत के मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस संघर्ष का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत को इस चुनौतीपूर्ण समय में अपनी कूटनीति और रणनीति के बीच संतुलन बैठाना होगा।

हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव से भारत के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। विशेषकर ईरान में चाबहार बंदरगाह और हाल ही में स्थापित इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) जैसी परियोजनाओं के बारे में जिसपर हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर पड़ सकता है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए

अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। मध्य पूर्व में हिज्बुल्लाह-इजरायल संघर्ष के बढ़ने से समुद्री व्यापार मार्गों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे होरमुज की खाड़ी और अरब सागर में जोखिम बढ़ सकता है। यदि ईरान, जो हिज्बुल्लाह का करीबी सहयोगी है, इस संघर्ष में शामिल हो जाता है, तो भारत की चाबहार में संचालित गतिविधियां खतरे में पड़ सकती हैं। प्रतिबंधों या ईरानी की सीधी भागीदारी से भारत के निवेश और परियोजनाओं में महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं
संघर्ष के परिणामस्वरूप वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है और जिन मार्गों से इसकी आपूर्ति होती है उसपर भी प्रभाव पड़ सकता है। जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर संकट आ सकता

है। चाबहार की खाड़ी में स्थित रणनीतिक स्थिति को देखते हुए किसी भी क्षेत्रीय अस्थिरता से इस महत्वपूर्ण ऊर्जा लिंक को खतरा हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप भारत को तेल की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पूरी इंपोर्ट चेन प्रभावित होगी।

इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC)

छ्पि, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक रणनीतिक विकल्प माना जाता है, के सुरक्षित संचालन के लिए मध्य पूर्व में स्थिरता की आवश्यकता है। हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा कर सकता है, जिससे इस कॉरिडोर की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। संघर्ष की स्थिति में इस कॉरिडोर से जुड़ी बुनियादी ढांचे, जैसे कि बंदरगाह, रेलवे,

और पाइपलाइनों के विकास पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को संतुलित करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इजरायल के साथ करीबी संबंध और कई अरब देशों और ईरान के साथ मजबूत रिश्तों को ध्यान में रखते हुए, भारत को एक नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना पड़ सकता है।

आर्थिक और रणनीतिक परिणाम

लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है। यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष से वैश्विक तेल की कीमतों में अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर तब जब भारत की तेल आयात पर निर्भरता अधिक है।



प्रवासन और शरणार्थी मुद्दे

संघर्ष की स्थिति में शरणार्थी संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे भारत के क्षेत्रीय हित प्रभावित हो सकते हैं, विशेषकर खाड़ी क्षेत्र में। इस एरिया में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। यदि स्थिति बिगड़ती है तो भारत को अफगानिस्तान, रूस-यूक्रेन और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में चलाए गए इवैकुएशन अभियानों की तरह एक और योजना शुरू करनी पड़ सकती है। सूत्रों के अनुसार, भारत इजरायल-हिज्बुल्लाह संघर्ष और इसके मध्य पूर्व पर पड़ने वाले प्रभाव का

आकलन कर रहा है। इन आकलनों के आधार पर भारत अपने व्यापार और ऊर्जा मार्गों को विविधतापूर्ण करने के प्रयासों को तेज कर सकता है, ताकि मध्य पूर्वी चोकपॉइंट्स पर निर्भरता कम हो सके। साथ ही, भारत इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने मजबूत संबंधों का लाभ उठाकर कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ा सकता है। क्षेत्रीय खिलाड़ियों जैसे कि सऊदी अरब और यूएई के साथ गठजोड़ को मजबूत करना भारत की रणनीतिक परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

भारत को विकसित बनाने के लिए कार्यबल में और 40 करोड़ महिलाओं को जोड़ने की जरूरत, रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत का लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, ऐसे में इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारत को अपनी महिला श्रम बल भागीदारी में पर्याप्त वृद्धि करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी को लगभग दोगुना करके 37 प्रतिशत से 70 प्रतिशत पर पहुंचाना जरूरी है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में 14 ट्रिलियन (14 लाख करोड़) अमेरिकी डॉलर का योगदान देने के लिए कार्यबल में अतिरिक्त 40 करोड़ महिलाओं को जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए वित्त वर्ष 2047 तक मौजूदा महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को 37 प्रतिशत से लगभग दोगुना करके 70 प्रतिशत तक पहुंचाना होगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार तब तक केवल 11 करोड़ महिलाओं के महिलाओं के श्रम बल में शामिल होने का अनुमान है। ऐसे में अर्थव्यवस्था से जुड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 14.5 करोड़ महिलाओं को कार्यबल से जोड़ने की जरूरत है।

भारत ने 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रखा है लक्ष्य

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, ऐसे में इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए इसे अपनी महिला श्रम बल भागीदारी में पर्याप्त वृद्धि करने की जरूरत है। भारत ने 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल कर खुद को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2047 तक भारत को अपनी वर्तमान महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को 37 प्रतिशत से लगभग दोगुना करके 70 प्रतिशत तक पहुंचाना होगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार तब तक केवल 11 करोड़ महिलाओं के महिलाओं के श्रम बल में शामिल होने का अनुमान है। ऐसे में अर्थव्यवस्था से जुड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 14.5 करोड़ महिलाओं को कार्यबल से जोड़ने की जरूरत है।

रिपोर्ट में पुरुषों और महिलाओं के बीच नौकरी की सुरक्षा के मामले में भारी असमानता का पता चलता है। इसके अनुसार कार्यबल से जुड़े

आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अपनी नौकरी खोने की आशंका सात गुना अधिक है। दूसरी ओर नौकरी छूटने पर उस स्थिति से फिर से नहीं उबर पाने की उबरने की आशंका महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ग्यारह गुना अधिक है।

महिलाओं के लिए उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने की जरूरत

सबसे पहले, प्लेटफॉर्म जॉब्स और डिजिटल माइक्रोवर्क के माध्यम से काम को फिर से परिभाषित करना महिलाओं के बीच रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। दूसरा, डिजिटल कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, गतिशीलता और डिजिटल पहुंच जैसी

बाधाओं को दूर कर श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी को बेहतर बनाया जा सकता है।

द नज प्राइज के निदेशक और प्रमुख कनिष्क चटर्जी ने कहा, 'भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिए बिना साकार नहीं हो सकते।' रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था में आई प्रगति को स्वीकार किया गया है लेकिन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए तत्काल और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, नज प्राइज टीम ने विभिन्न क्षेत्रों के पीएलएफएस डेटा का गहनता से अध्ययन किया।

2020 में लगभग आधी महिलाएं कार्यबल से हो गई बाहर

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक, 2019 में कार्यरत लगभग आधी महिलाएं कार्यबल से बाहर हो गई थीं। महिलाएं मुख्य रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे कृषि और विनिर्माण, जहां उन्हें सीमित वृद्धि मिल पाती है। कोविड महामारी के कारण ये मुद्दे और बढ़े। कई ग्रामीण महिलाओं को आय में कमी या परिवार में मुख्य रूप से कमाने वाले व्यक्ति की नौकरी छूटने के कारण फिर से काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह महिला रोजगार की नाजुकता को सामने लाता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, रिपोर्ट में महिला श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ाने के लिए तीन रास्ते बताए गए हैं।

AGM से पहले रिलायंस के 35 लाख निवेशकों के लिए गुड न्यूज, हर शेयर पर रु. 400 का फायदा!

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक गुरुवार को हो रही है। कंपनी के 35 लाख निवेशकों के साथ-साथ शेयर मार्केट को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। हालांकि पिछली एजीएम के बाद से कंपनी के शेयर का प्रदर्शन बेंचमार्क इंडेक्सेज के मुकाबले कम रहा है। इस दौरान रिलायंस के शेयरों में करीब 21% तेजी आई है जबकि सेंसेक्स में लगभग 25% की वृद्धि हुई। इसके बावजूद रिलायंस का शेयर निवेशकों के लिए काफी फायदेमंद रहा है क्योंकि इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली लिस्टेड कंपनी है। इस साल अब तक आरआईएल के शेयरों ने 17% की बढ़त के साथ बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी तुलना में सेंसेक्स में इस साल अब तक लगभग 13% की वृद्धि हुई है। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि रिलायंस की एजीएम में कंपनी के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी रिटेल और डिजिटल बिजनेस की लिस्टिंग के बारे में कोई घोषणा कर सकते हैं। हालांकि पिछले साल भी निवेशक यही उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन अंबानी ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की। जेफरीज के विश्लेषकों को उम्मीद है कि जियो अगले साल करीब 112 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ लिस्ट हो सकती है। साथ ही निवेशकों को उम्मीद है कि अंबानी O2C (तेल से लेकर रसायन) बिजनेस में रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री पर भी कोई खुलासा कर सकते हैं।

ग्रोथ का इंजन- इसके अलावा निवेशक न्यू एनर्जी बिजनेस पर अपडेट की उम्मीद कर रहे हैं। विश्लेषकों को लगता है कि यह कंपनी के ग्रोथ का अगला इंजन होगा। रिलायंस जामनगर में एक मेगा ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स विकसित कर रही है। इसमें सोलर पीवी, एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर, फ्यूल सेल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गीगा फैक्ट्रीज बनाने की योजना है। हालांकि एनालिस्ट्स को लगता है कि इसमें निवेश की रफ्तार धीमी है। निवेशक न्यू एनर्जी बिजनेस में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर अपडेट की उम्मीद कर रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्वोरिटीज ने कहा कि आरआईएल अगले दशक में अपने लिए पिछले 40 वर्षों की तुलना में एक अलग भविष्य देखता है। बोर्ड में अगली पीढ़ी के तीन सदस्यों को शामिल किया गया है। साथ ही मुकेश अंबानी कम से कम अगले 5 साल के लिए चेयरमैन बने रहेंगे। एजीएम से पहले ग्लोबल ब्रोकरेज बर्नस्टीन ने आरआईएल के शेयर को आउटपरफॉर्म रेटिंग के साथ इसका टारगेट प्राइस 3,440 रुपये कर दिया है। इसी तरह मॉर्गन स्टेनली ने भी इसका टारगेट प्राइस 3,416 रुपये रखा है। बुधवार को कंपनी का शेयर फ्लैट 2995.75 रुपये पर ट्रेड बंद हुआ।

7 सितंबर को मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी

बप्पा की पूजा के समय न करें कोई गलती

गणेश चतुर्थी से हर साल गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार, भगवान गणेश सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले और शुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है और दस दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। हर साल भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर अगस्त या सितंबर के बीच आता है। गणेश चतुर्थी के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय कर लिए जाएं, तो कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है।



डॉ. आर.डी. आचार्य

9009369396

ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

गणेश चतुर्थी पर इन बातों का रखें ध्यान

बप्पा की विधिवत पूजा

गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें मोदक, लड्डू और ताजे फूल चढ़ाएं। चतुर्थी के दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

जरूरतमंदों की मदद करें

गणेश चतुर्थी के अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन या कपड़े दान करें। इस दिन दान करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा मिलती है।

इन मंत्रों का करें जाप

गणेश चतुर्थी के दौरान 'ओम गं गणपतये नमः' या 'ओम विष्णुश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए यह मंत्र उपयोगी है।

बप्पा को भोग लगाएं

भगवान गणेश को घर में बने मोदक का भोग लगाएं। मोदक बप्पा का प्रिय प्रसाद माना जाता है। ऐसा करने से गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है।

गणेश चालीसा का पाठ

गणेश चतुर्थी पर गणेश चालीसा का पाठ करें। इस दिन गणेश चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह आपको जीवन में चल रहे कष्टों से राहत मिलेगी।



पंडित कपिल पाराशर

ज्योतिष आचार्य

वास्तु विशेषज्ञ

6261493070

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका व्रत की परंपरा है। इस बार हरतालिका तीज 6 सितंबर को शुक्रवार के दिन हस्त नक्षत्र की साक्षी में आ



पं. श्री रमेशचंद व्यास

(चैनपुरा वाले)
ज्योतिषयाचार्य एवं
रत्न विशेषज्ञ
मो. 9826345104

हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू महीने के अंतिम दिन को अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा, स्नान-दान आदि जरूर करना चाहिए। सभी अमावस्याओं में मौनी और सोमवती अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान के साथ पितृ पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक

किस दिन है सोमवती अमावस्या? पितरों के तर्पण के लिए महत्वपूर्ण है यह तिथि

मान्यताओं के अनुसार, सोमवती अमावस्या के दिन पूजा-पाठ के साथ कुछ विशेष उपाय करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ग्रह दोष और पितृ दोष आदि से भी छुटकारा मिलता है। आइए, जानते हैं कि सोमवती अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी और इस दिन क्या करना चाहिए।

सोमवती अमावस्या तिथि 2024

भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 बजे शुरू होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 3 सितंबर 2024, सुबह 7:24 बजे होगा।

सोमवती अमावस्या पर क्या करें

अमावस्या के दिन गंगा या अन्य

पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। यह आवश्यक माना जाता है।

इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में अमावस्या पर गरीबों या जरूरतमंदों को जरूरी सामान दान करें।

सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करें। इस दिन पितृ गायत्री मंत्र या पूर्वजों को समर्पित मंत्रों का जाप करना चाहिए।

इस दिन धार्मिक ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन अधिकतर समय धार्मिक कार्यों और पूजा-पाठ आदि में व्यतीत करना चाहिए।

इस दिन बड़ों का सम्मान करें और सभी से प्रेमपूर्वक व्यवहार करें।

इस दिन मंदिर या धार्मिक स्थान पर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए।

सोमवती अमावस्या पर क्या नहीं करें

मांसाहारी भोजन या शराब आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए।

इस दिन चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना वर्जित माना जाता है।

इस दिन किसी भी जीव-जंतु को परेशान न करें।

इस दिन किसी का अनादर न करें। इस दिन कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जैसे शादी या सगाई आदि न करें। इस दिन पितृ दोष लगने वाला कोई काम न करें।

पनौती से क्या समझते हैं आप, शनि की पनौती में क्या होता है?



पं. राजेश वैष्णव

शनि उपासक ज्योतिष
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

पनौती शब्द का अर्थ अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होता लेकिन जब हमारा कोई काम नहीं बनता तो अक्सर हम पनौती शब्द का प्रयोग करने लग जाते हैं। कहने का मतलब की इस शब्द का इस्तेमाल हम बुरी किस्मत के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पनौती शब्द का संबंध शनि से जोड़ा जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण

शनि देव से पनौती का संबंध

पनौती शब्द का संबंध ज्योतिष विषय में अलग होता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि के साढ़े साती के

बारे में हर कोई जानता है। शनि जब किसी राशि में मौजूद रहते हैं तो उससे अगली और पिछली राशि पर साढ़े साती का असर रहता है। शनि एक राशि में करीब 2.5 वर्ष तक रहते हैं इसलिए जब किसी व्यक्ति की साढ़े साती शुरू होती है तो करीब 7 साल तक उस राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव रहता है।

शनि की साढ़ेसाती को ही पनौती कहा जाता है। माना जाता है कि शनि की साढ़ेसाती जब किसी को लगती है तो उस व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि पनौती छोटी और बड़ी दो तरह की होती है।

सरल शब्दों में कहा जाए तो साढ़ेसाती को बड़ी चुनौती कहा जाता है। जबकि शनि की ढैय्या जातक के जन्म राशि से चौथे और अष्टम भाव में शनि के आने से लगती है तो उसे छोटी पनौती कहा जाता है।

पनौती का मतलब अशुभ और खराब

शनि देव की साढ़ेसाती या पनौती सदैव अशुभ नहीं मानी जाती है। शनि देव ने शिव भगवान की पूजा आराधना की जिससे खुश होकर भगवान शिव ने शनि देव को नवग्रहों का न्यायाधीश का बना दिया। इसलिए जब शनि की दशा

और शनि का गोचर लगता है तो शनि देव व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से दंडित या पुरस्कार करते हैं। इसलिए शनि की साढ़ेसाती को अशुभ शकुन कहना गलत होता है।

पनौती का संबंध भद्रा से भी

भद्रा शनि देव की बहन है। ब्रह्मा जी ने भद्रा का समय तीनों लोकों निर्धारित कर रखा है। भद्रा के वक्त किसी भी तरह का शुभ काम नहीं किया जाता है। क्योंकि भद्रा में किये गए कामों का परिणाम खराब होता है।

कब मनाई जाएगी हरतालिका तीज... इस बार पति को दीर्घायु प्रदान करने वाले शुभ योग

रही है। विशेष यह है कि इस बार तीज पर पति को दीर्घायु प्रदान करने वाले शुभ योग विद्यमान रहेंगे। धर्मशास्त्र के जानकारों के अनुसार इन योग शिव और माता पार्वती का पूजन मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। सौभाग्यवती महिलाओं को इस दिन यथाविधि व्रत तथा अगले दिन पारणा करना चाहिए।

27 योगों में से एक शुक्ल योग

पं. कपिल पाराशर ने बताया हरतालिका तीज 6 सितंबर को शुक्रवार के दिन हस्त नक्षत्र उपरांत चित्रा नक्षत्र एवं शुक्ल योग की साक्षी में आ रही है। शुक्रवार के दिन हस्त नक्षत्र की साक्षी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। वहीं 27 योगों में से एक शुक्ल योग तृतीया तिथि पर विशेष महत्वपूर्ण बताया जाता है। इस योग में हरतालिका की पूजा

पति को दीर्घायु व पुत्र पौत्र की वृद्धि को देने वाली मानी जाती है।

शुक्ल योग की अधिष्ठात्री माता पार्वती

इस बार हरतालिका तीज पर्व पर शुक्ल योग इसलिए विशेष भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस योग की अधिष्ठात्री माता पार्वती है। हरतालिका तीज व्रत का कथासार देखें तो शिव पार्वती के संयुक्त क्रम की पूजन पौराणिक कथाओं में प्राप्त होती है। पंडितों के अनुसार इस

कथा श्रवण से पति की दीर्घायु एवं परिवार में सुख शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। पंडितों का यह भी कहना है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, उन्हें भी यह व्रत उत्तम वर की प्राप्ति हेतु करना चाहिए।

रवि योग भी इसी दिन

किसी भी व्रत, पर्व या त्यौहार पर यदि रवि योग की साक्षी हो तो उस व्रत का महत्व बढ़ जाता है। इस बार हरतालिका तीज पर रवि योग का महासंयोग भी बन रहा है।

बुधादित्य योग की भी साक्षी

ग्रह गोचर के आधार पर देखें तो हरतालिका तीज वाले दिन सिंह राशि पर सूर्य व बुध का परिभ्रमण रहेगा, बुध आदित्य नाम के योग का निर्माण करेगा। यह श्रेष्ठ योग व्रत, त्यौहार में अपना विशेष प्रभाव रखता है। इस योग की साक्षी व्यक्तित्व को प्रबल तथा संबंधों को प्रगाढ़ करती है। इस दृष्टि से भी यह त्योहार विशेष योग वाला है।

फेस्टिव सीजन से पहले ही 3.5% तक सस्ती मिलेगी कारें लेकिन उसके लिए करना होगा यह काम

नई दिल्ली। एजेंसी

गाड़ी खरीदने को योजना बना रहे लोगों के लिए त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले गुड न्यूज है। पैसेंजर कार, लग्जरी गाड़ी और हेवी ट्रांसपोर्ट वीकल बनाने वाली कंपनियों ने ग्राहकों को 1.5% से लेकर 3.5% छूट देने पर सहमति जताई है। लेकिन यह छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अपनी पुरानी गाड़ी को स्कूप करके नई गाड़ी खरीदेंगे। लग्जरी कार बनाने वाली कुछ कंपनियां तो लगभग 25,000 रुपये तक की छूट देने को तैयार हैं। सूत्रों का कहना है कि दूसरी कंपनियां भी छूट की अधिकतम सीमा तय कर सकती हैं। ऑटो इंडस्ट्री और सरकार आज इस बारे में ज्यादा जानकारी की घोषणा कर सकते हैं। मार्च

2021 में स्कूपिंग पॉलिसी को लॉन्च किए जाने के बाद से रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ग्राहकों को अपने पुराने वाहनों को स्कूप करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कीमत और जीएसटी में छूट जैसी रियायतों पर जोर दे रहे हैं। साल 2022 में मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल यूनियनों को एक सलाह भेजी कि वे अपने सदस्यों को स्कूप किए गए वाहनों के बदले बिक्री मूल्य पर 5% तक की छूट देने के लिए कहें। लेकिन तब इंडस्ट्री ने इसे नजरअंदाज कर दिया था और अपनी सुविधा के मुताबिक व्यवस्था चुनी थी। सरकार ने 60 रजिस्टर्ड वीकल स्कूपिंग फैसिलिटीज और 75 ऑटोमैटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की पहल की है।

डीलरों के पास इवेंट्री बढ़ी

अप्रैल-जून तिमाही में देश में कारों की रफ्तार मामूली रही है जबकि प्रॉडक्शन बढ़ा है। FADA का कहना है कि उसके मेंबर्स डीलरों के पास करीब 730,000 गाड़ियों की इवेंट्री है जो दो महीने की बिक्री के बराबर है। हालांकि SIAM का दावा है कि यह संख्या 400,000 यूनिट के करीब है। सूत्रों का कहना है कि अमूमन भारतीय बाजार में पहली तिमाही में डिमांड कम रहती है लेकिन इस बार डिमांड उम्मीद से काफी कम रही। आम चुनावों, भारी बारिश और लू इसका कारण हो सकता है। माना जा रहा है कि इवेंट्री को खपाने के लिए कंपनियां आने वाले दिनों में कीमतों में कमी कर सकती हैं।

फिजी से पानी, चीन से जूस, ऑस्ट्रेलिया से मीट, कनाडा से मशरूम... भारत से क्या मंगाता है अमेरिका

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। दूर-दूर तक कोई देश उसके मुकाबले में नहीं है। अमेरिका के लगभग सभी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं। दुनिया का हर छोटा-बड़ा देश अमेरिका के साथ अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका का बाजार बहुत बड़ा है। अमेरिका के बाजार में ज्यादातर चीजें इम्पोर्टेड हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका सबसे ज्यादा पानी फिजी से मंगाता है। वह अपने पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको से सबसे ज्यादा खाने-पीने का सामान मंगाता है। चीन कई साल तक उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा। लेकिन पिछले कुछ साल से दोनों देशों को रिश्तों में तलखी आई है।

यहां हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका किस देश से खाने-पीने का क्या सामान मंगाता है। अमेरिका अपने पड़ोसी देश कनाडा से मशरूम, पशु मीट, सुअर का मीट, मछली, लॉबस्टर, केकड़े, कैनोला ऑयल, गेहूं, मक्का, ओट्स, जो और मैपल सिरप मंगाता है। इसी तरह टमाटर, एवोकाडो, शिमला मिर्च, क्रेनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रैस्पेरीज, ककड़ी, ब्रोकोली, तरबूज, आम, एस्पेरेगस, नींबू, प्याज, पालक, लेट्यूस, अखरोट और चीनी का सबसे ज्यादा आयात मेक्सिको से किया जाता है। अमेरिका में भेड़ की सबसे ज्यादा मीट ऑस्ट्रेलिया से आता है जबकि ब्राजील से ओरेंज जूस का सबसे ज्यादा आयात किया जाता है। चीन से सबसे ज्यादा ऐपल जूस और

फ्रोजन फिश आती है। चिली से अंगूर और पोल्ट्री का आयात होता है जबकि कोलंबिया से कच्ची कॉफी आती है।

भारत से क्या मंगाता है

इसी तरह कोस्टारिका अमेरिका को अन्नानास का सबसे बड़ा सप्लायर है जबकि आइवरी कोस्ट से कॉफी बीन्स आती है। ग्वाटेमाला से केला और तरबूज आता है जबकि इंडोनेशिया पाम ऑयल और कोको बटर का एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका को बटर सप्लाय के मामले में आयरलैंड सबसे आगे है जबकि इटली से ऑलिव ऑयल, सॉल्टेड स्वाइन मीट और चीज आता है। अमेरिका को सबसे ज्यादा दूध की सप्लाय न्यूजीलैंड से होती है। इसी तरह नीदरलैंड्स से कोको पाउडर आता है। स्पेन रिफाईंड ऑलिव ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर

है, स्विट्जरलैंड से रोस्टेड कॉफी आती है, थाईलैंड से चावल आता है और वियतनाम काली मिर्च और काजू का सबसे बड़ा सप्लायर है।

जहां तक भारत का सवाल है तो अमेरिका सबसे ज्यादा झींगा मछली भारत से मंगाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में अमेरिका ने भारत से 2,97,571 मीट्रिक टन फ्रोजन झींगे का आयात किया। इस दौरान भारत का सीफूड एक्सपोर्ट ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया। भारत ने 2023-24 में 17,81,602 मीट्रिक टन सीफूड का एक्सपोर्ट किया जिसकी कीमत रु. 60,523.89 करोड़ रुपये रही। अमेरिका के बाद चीन, यूरोपीय यूनियन, साउथईस्ट एशिया, जापान और मिडल ईस्ट भारतीय सीफूड के सबसे बड़े बाजार हैं।

भारतीय नौसेना में घातक अरिघात पनडुब्बी की एंट्री 750 Km की रेंज, चीन-पाक की हर चाल होगी नाकाम

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय नौसेना गुरुवार को अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को शामिल करेगी। यह पनडुब्बी INS अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। पहली पनडुब्बी INS अरिहंत 2009 में नौसेना में शामिल हुई थी। यह पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के शीर्ष अधिकारी की मौजूदगी में नौसेना में शामिल होगी।

आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी। भारतीय नौसेना जल्द ही तीसरी पनडुब्बी को भी शामिल करने वाली है। दो और पनडुब्बियां साल 2035-36 तक तैयार हो जाएंगी। भारतीय नौसेना ने इन दोनों पनडुब्बियों से लंबी दूरी की परमाणु

मिसाइलों का परीक्षण किया है। आईएनएस



अरिघात, भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, जो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आईएनएस अरिघात सबमरीन भारतीय नौसेना की अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। अरिहंत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 'शत्रु का नाश करने वाला'। यह नाम पनडुब्बी

के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। कई विकल्पों में से 'अरिहंत' नाम को चुना गया था। यह नाम सभी स्तरों पर स्वीकृत हुआ। यह नाम अपनी सूक्ष्मता और दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने में सटीकता के कारण चुना गया था।

अरिहंत की तरह अरिघात भी 750 Km की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस होगी। अरिघात आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। अरिघात भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अरिघात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी प्रकार सक्षम है जिस तरह अरिहंत। अरिहंत से के -15 की सफल टेस्टिंग की जा चुकी है। इसके साथ ही भारत दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन चुका है।

OPPO इंडिया ने नया F27 5G लॉन्च किया

ई-स्टोर, फिलपकार्ट, अमेज़न और मेनलाईन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध
इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

OPPO इंडिया ने F27 5G लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन में OPPO की नई हैलो लाइट (Halo Light) है, स्मार्टफोन के रियर में एलईडी का एक घेरा, जो संगीत के साथ जगमगाता है। साथ ही इसमें एडवांस्ड एआई कैमरा फीचर्स भी हैं, जिनकी मदद से आप पार्टी की बेहतरीन तस्वीरें लेकर उन्हें अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। OPPO F27 5G दो रंगों – अंबर ऑरेंज (Amber Orange) और एमराल्ड ग्रीन (Emerald Green) में मिलेगा। इसके 128GB वैरिएंट का मूल्य 22,999 रुपये और 256GB वैरिएंट का मूल्य 24,999 रुपये होगा।

सुपर.मनी ने लॉन्च किया नया क्रेडिट फर्स्ट यूपीआई एप

बीटा फेज में 10 मिलियन लेनदेन का आंकड़ा पार
आईपीटी नेटवर्क

क्रेडिट-फर्स्ट यूपीआई सर्विस प्लेटफॉर्म सुपर.मनी ने बीटा फेज की सफलता के बाद आज अपना आधिकारिक एप लॉन्च किया। बीटा फेज के दौरान एप के करीब 10 लाख डाउनलोड हुए और 1 करोड़ से ज्यादा लेनदेन हुए। ये आंकड़े तेजी से एप की बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाते हैं। सुपर.मनी ने अपनी तरह के पहले क्रेडिट ऑन यूपीआई सॉल्यूशन का परीक्षण भी पूरा कर लिया है। अब इसके लिए वेतलिस्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है। सुपर मनी का पहला सॉल्यूशन एक रुपे क्रेडिट कार्ड है, जो यूपीआई पर इंटरैक्ट बियरिंग वॉलेट की तरह काम करता है। इसे दुनिया में अपनी तरह का पहला सॉल्यूशन माना जा रहा है।

सुपर.मनी के संस्थापक एवं सीईओ प्रकाश सिकारिया ने कहा सुपर.मनी के एप की लॉन्चिंग का यह समय बहुत अनुकूल है। एप को ऐसे समय में लॉन्च किया जा रहा है, जबकि देश में लगातार तीसरे महीने यूपीआई लेनदेन का आंकड़ा 20 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है हमारा बीटा फेज सुपर.मनी से जुड़े अनुभव को आकार देने में अहम रहा है। इससे खासतौर से यह सामने लाने में मदद मिली कि हम किस तरह से यूपीआई पर क्रेडिट को नए सिरे से परिभाषित करेंगे।

अब फोनपे ने अपने प्लेटफॉर्म पर UPI क्रेडिट लाइन को भी चालू किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

फोनपे ने अपने प्लेटफॉर्म पर UPI पर क्रेडिट लाइन लॉन्च करने की घोषणा की। जिन उपभोक्ताओं ने अपने बैंकों से क्रेडिट लाइन का सुविधा लिया है, वे अब इन क्रेडिट लाइनों को फोनपे पर ळछ से लिंक करके आसानी से मर्चेट पेमेंट कर पाएंगे। यह सुविधा उपभोक्ताओं को, लाखों व्यापारियों के साथ खरीदारी करने में सक्षम बनाएगी। साथ ही, उन्हें शॉर्ट-टर्म क्रेडिट भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें अपने मासिक खर्चों को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिल सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ळछ के दायरे का विस्तार किया है, जिससे UPI में, प्री- अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन को शामिल किया जा सके। इसे 'UPI पर क्रेडिट लाइन' भी कहा जाता है। इससे ग्राहक अब बैंकों से क्रेडिट लाइन प्राप्त कर सकते हैं और अपने UPI ऐप्स के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करने वाले मर्चेट की संख्या तेजी से बढ़ेगी।

उपभोक्ताओं के अलावा, फोनपे पेमेंट गेटवे (PG) पर मर्चेट को भी यह विकल्प दिया गया है कि वे चेकआउट के समय अपने ग्राहकों को पेमेंट का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकें। इससे खरीदारी करने में रुकावटें कम होती हैं। साथ ही ग्राहक कार्ट में प्रॉडक्ट को जोड़ने के बाद इसको ऐसे ही न छोड़कर खरीदारी के लिए आगे बढ़ते हैं। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए मर्चेट को फोनपे पेमेंट गेटवे की मदद से, पेमेंट के विकल्प के रूप में 'ळछ पर क्रेडिट लाइन' जोड़नी होगी।

साबूदाने का निर्यात बढ़ेगा: गोपाल साबु

इंदौर/ सेलम। आईपीटी नेटवर्क

इस वर्ष साबूदाने के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। यह कहना है साबूदाने के निर्माण, विक्रय और विपणन के कारोबार से 45 से अधिक वर्षों से जुड़े व्यवसायी और और एफ एम सी जी कंपनी साबू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री गोपाल साबु का। श्री साबु ने बताया कि कसावा जमीकंद की पैदावार इस बार अनुमान से बेहतर क्वालिटी की आई है और उत्पादन भी बम्पर

हुआ है, जिसके चलते कच्चे माल के दाम काफी कम रहने की संभावना है और इस से बेहतरीन क्वालिटी साबूदाने की लागत कम रहेगी। वैश्विक नजरिए से भाव प्रतिस्पर्धात्मक होने पर इस वर्ष साबूदाने का निर्यात बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है। साबूदाना क्षेत्र में आरम्भ से ही साबु ट्रेड कई मित्र देशों में सर्वाधिक भारतीय साबूदाना निर्यात करने वाली कम्पनी जानी जाती है।

श्री साबु ने बताया कि वर्तमान

में सेलम में उत्पादकों, व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के पास अनुमानतः साबूदाने का करीब 7 से 8 लाख बोरी (90 किलो भर्ती) तैयार स्टॉक है और नया माल बहुतायत में आ जाने से नवरात्रि पर अच्छी खपत की संभावना के बावजूद भाव स्थिर रह सकते हैं या कमी आ सकती है।

श्री साबु ने आगे कहा कि भारत में साबूदाना की बढ़ती मांग के कारण बाजार के आकार में वृद्धि हो रही है। साबूदाने की

खिचड़ी, खीर जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों की लोकप्रियता बाजार को बड़ा करती ही है, साथ ही, प्रयोगधर्मी महिलाएं जो साबूदाने से तरह-तरह के नाश्ते और व्यंजन बनाती हैं, वह मांग भी इसमें बड़ा योगदान देती है। साबूदाने का पकने में आसान होना, मसालों के मिलने पर स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य उत्पाद बन जाने का गुण इसकी लोकप्रियता बढ़ा देता है, जो बड़े बाजार के लिए अवसर है।

भारतपे अपने मर्चेट पार्टनर्स को सुरक्षित लोन प्रदान करेगा

ओटीओ कैपिटल और वोल्ट मनी के साथ साझेदारी की घोषणा की भारतपे टू-व्हीलर लोन और म्यूचुअल फंड के बदले लोन की सुविधा प्रदान करेगा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारतपे, भारत की एक प्रमुख फिनटेक कंपनी है। भारतपे ने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी मर्चेट पार्टनर्स के लिए सुरक्षित लोन की पेशकश की है। पहले चरण में कंपनी ने अपने मौजूदा मर्चेट पार्टनर्स के लिए दो पहिया लोन और म्यूचुअल फंड्स के जरिए लोन (LAMF) देने की सुविधा शुरू की है। भारत पर ने दो पहिया लोन के लिए ओटीओ कैपिटल के साथ और म्यूचुअल फंड्स पर लोन के लिए वॉल्ट मनी के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी अगले चरण में ऐसे मल्टी-प्रोडक्ट और मल्टी-लेंडर आफरिंग में विस्तारित करने की योजना बना



रही है।

भारत पे के मर्चेट पार्टनर्स अब ओटीओ कैपिटल के माध्यम से अपने अगले दो पहिया वाहन के लिए 2.5 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जिसका ब्याज भी काफी कम होने वाला है। लोन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है

और मर्चेट 12 से 48 महीना के बीच किसी भी अवधि को चुन सकते हैं। इसके अलावा वोल्ट मनी के साथ पार्टनरशिप के तहत मर्चेट म्यूचुअल फंड्स पर भी 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं।

इस सुविधा की लॉन्चिंग पर भारत पे की सीईओ नलिन नेगी

ने कहा - 'भारतपे ने 2018 में लाखों ऑफलाइन मर्चेट पार्टनर्स को नए जमाने के फिनटेक उत्पादों से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरुआत की थी। 2019 में हमने असुरक्षित लोन की पेशकश और 0.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर एमएसएमई क्रेडिट गैप को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वह हमारी कंपनी के विकास में अड़चन साबित हुआ। लेकिन अब हमारी सुरक्षित लोन की सुविधा से हमारे क्रेडिट पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी। मैं ओटीओ कैपिटल और वॉल्ट मनी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे 1.3 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने में मदद की।'

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 'निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड' को लॉन्च किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (NIMF) के एसेट मैनेजर, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (NAM इंडिया) ने 'निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड' के लॉन्च की घोषणा की, जो बिल्कुल निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स की तरह/उसकी ट्रैकिंग करने वाली एक ओपन-एंडेड स्कीम है। यह पैसिव फंड अपने आप में अनोखा है, जो निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को ट्रैक करता है। ये फंड वाकई बिल्कुल अलग तरह की पेशकश है, जो निवेशकों को अलग-अलग क्षेत्रों की 500 कंपनियों के स्टॉक में निवेश का अवसर प्रदान करता है, जिसके तहत पोर्टफोलियो



में हरेक स्टॉक का मान बराबर होता है। आम तौर पर यह बाजार-पूँजीकरण पर आधारित भारित सूचकांकों से जुड़े संकेन्द्रण के जोखिम को कम करने वाला साधन है, और इससे बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार

के विकास में भाग लेने का शानदार अवसर मिलता है। जो निवेशक भारत के विकास के इस सफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें बड़े, मध्यम और छोटी पूंजी वाली कंपनियों सहित बड़े पैमाने पर बाजार में निवेश करना चाहिए, जो लंबे समय में विकास को गति दे सकते हैं। निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स पूरी तरह से विविधतापूर्ण है, जिसमें 21 अलग-अलग क्षेत्रों की 500 कंपनियों के शेयरों में निवेश किया गया है। यह इंडेक्स लार्ज-कैप स्टॉक में 20%, मिड-कैप स्टॉक में 30% और स्मॉल-कैप स्टॉक में 50% निवेश उपलब्ध कराएगा, जो बेहद नायाब है क्योंकि बाजार में मौजूद दूसरे फंड्स में ऐसा संयोजन शायद ही कहीं मिलेगा।

सैमसंग त्योंहारों से पहले भारत में लॉन्च करेगा 10 एआई वाशिंग मशीनें

गुरुग्राम। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैंड, सैमसंग ने इस साल त्योंहारों के सीजन के लिये 10 वाशिंग मशीनें पेश करने की अपनी योजना की घोषणा की है। कंपनी ने हाल ही में अपनी आगामी फ्रंट-लोड एआई-पावर्ड वाशिंग मशीनों का टीज़र दिखाया था। यह मशीनें इस महीने के आखिर में लॉन्च की जाएंगी। नई एआई-पावर्ड वाशिंग मशीनें भारतीय ग्राहकों के लिए कंपनी के घरेलू उपकरणों की प्रीमियम बीस्पोक एआई रेंज का हिस्सा हैं। इन मशीनों में बेहतर कनेक्टिविटी दी गई है और यह इंटेलिजेंट तथा सहज समाधानों के साथ शानदार अनुभव देती हैं। यह सभी मिलकर स्मार्ट घर के अनुभव में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

एक वक्तव्य में सैमसंग इंडिया ने कहा, "इस साल त्योंहारों के सीजन से पहले सैमसंग भारत में निर्मित एआई-पावर्ड वाशिंग मशीनों की एक रोमांचक श्रृंखला लॉन्च करेगी। नई श्रृंखला में 10 मॉडल होंगे और इनमें मौजूद एआई इनोवेशन कपड़े धोने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। यह सीरीज लॉन्ड्री के बाजार में एक गेम चेंजर बन सकती है और इससे सैमसंग इंडिया की वाशिंग मशीनों के पोर्टफोलियो का विस्तार होगा।" सैमसंग इंडिया ने कहा कि जल्द ही लॉन्च होने जा रही ये वाशिंग मशीनें कपड़े धोने में लगने वाली मेहनत को करेंगी और ये एआई-पावर्ड फीचर्स से लैस होंगी। इससे यूजर्स की 'लाइफस्टाइल' बेहतर हो जाएगी। कुल मिलाकर यूजर्स का अनुभव ज्यादा 'स्मार्ट', बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल' हो जाएगा।

सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी वॉच में इरेगुलर हार्ट रिदम नोटीफिकेशन का फीचर पेश किया

गुरुग्राम। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैंड सैमसंग ने गैलेक्सी वॉच के लिए सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप पर इरेगुलर हार्ट रिदम नोटीफिकेशन (IHRN) फीचर पेश करने की घोषणा की है। ऐप के मौजूदा ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ, यह नया फीचर एट्रियल फ़िब्रिलेशन (AFib) का संकेत देने वाली हार्ट रिदम का पता लगाने में मदद करता है। इससे गैलेक्सी वॉच पहनने वालों को उनके हृदय की सेहत के बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी मिलती है। सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप में एक्टिव होने के बाद, धीरे-धीरे फीचर गैलेक्सी वॉच के बायोएक्टिव सेंसर का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड में अनियमित हृदय गति (इरेगुलर हार्ट रिदम) की लगातार जांच करता है। अगर लगातार माप की एक निश्चित संख्या अनियमित पाई जाती है, तो गैलेक्सी वॉच अपने यूजर्स को संभावित AFib एक्टिविटी की चेतावनी देता है और यूजर को अधिक सटीक माप के लिए अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके ईसीजी लेने की सलाह देता है। मौजूदा रक्तचाप और हृदय गति की निगरानी के साथ, यह नया फीचर यूजर्स को उनके हृदय के स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा गहन जानकारी प्रदान करता है।

उदयपुर जिक सिटी में होने वाली वेदांता जिक सिटी हाफ मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

उदयपुर। आईपीटी नेटवर्क

कुपोषण से बचाव के संदेश के साथ हिंदुस्तान जिक लिमिटेड वेदांता जिक सिटी हाफ मैराथन उदयपुर में 29 सितंबर को आयोजित करेगा। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन और डिस्टेंस रेस के आधिकारिक सदस्य के रूप में इस आयोजन को एआईएमएस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह वैश्विक स्तर पर सूचीबद्ध मैराथन है ए जो वैश्विक मंच पर इसके महत्व को बढ़ाता है।

वेदांता जिक सिटी हाफ मैराथन का मुख्य आकर्षण इसका लुभावना मार्ग होगा जो अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित फतेह सागर झील के चारों ओर है। प्रतिभागी उदयपुर की समृद्ध विरासत के साथ रूबरू होंगे जिसमें महाराणा प्रताप स्मारक जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों सहैलियों की बाड़ी और नीमच माता मंदिर पहाड़ी से गुजरेगा। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर कूल रन 10 किलोमीटर और डीम रन 5 किलोमीटर की होगी। यह आयोजन दुनिया भर के पेशेवर और शौकिया धावकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है।

अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।